छिंदवाड़ा
सोमवार, 2 फरवरी, 2026
वर्ष 25, अंक 300
पृष्ठ 12
मूल्य रु.5.00
www.navabharat.net

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

बजट 2026-27

- पिछले साल से 9 प्रतिशत इस बार अधिक बजट
- एमएसएमई को 10 हजार करोड़, अतिरिक्त 4 हजार करोड़
- 800 जिलों में लड़कियों के लिए बनेंगे हॉस्टल
- 5 साल में ट्रेड होगा दुगुना

आत्मनिर्भर भारत के लिए ‘खुशियों’ का पिटारा

आर्थिक दिशा को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में 2026-27 का आम बजट पेश किया. बजट में विशेष तौर पर देश के युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया. इसी के साथ बजट में ‘विकसित भारत 2047’ में सपनों के भारत के तस्वीर की झलक दिखी. वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बार नवमीं बार बजट पेश किया, जो कि देश में महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है. ये देश और दुनिया के लिए बड़ी मिसाल साबित हुई. वे 85 मिनट तक बोलीं, टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें इस बार में बजट में पहली बार कही गई. इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाददेश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

समझते है क्या होता है बजट

बजट मूल रूप से सरकार का वह रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसमें वह देश को बताती है कि आने वाले एक साल में उसकी कुल कमाई कितनी होगी और उस पैसे को किन-किन मदों में खर्च किया जाएगा। बजट 2026 में सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्रों पर बना हुआ है।

क्या होगा सस्ता

- 7 गंभीर रोगों की दवाएं
- कैंसर की 17 दवाएं
- शुगर की दवाई
- विदेश यात्रा
- सीएनजी और बायोगैस
- स्मार्टफोन और टैबलेट होंगे सस्ते

क्या होगा महंगा

- शराब
- स्कैप
- खनिज
- वायदा कारोबार

बजट की बड़ी घोषणाएं

- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- – कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया। अभी 5 प्रतिशत शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री।
- डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़, यानी 15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी। हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल 2.19 लाख करोड़ खर्च होंगे, यानी 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। इनमें मुंबई -पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी।
- 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।
- 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान।
- 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी।
- करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।

किसको कितना मिला बजट?

- वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट भारत की आर्थिक दिशा को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस बार

का कुल बजट 53.47 लाख करोड़ रुपए का है। अगर इसकी तुलना पिछले साल (2025-26) के बजट अनुमानों से की जाए, तो इसमें 5.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला देश की सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए सबसे अधिक 7,84,678.28 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- गृह मंत्रालय को आंतरिक सुरक्षा और राज्यों की पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2,55,233.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण को गरीबों को मुफ्त अनाज और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2,39,521.37 करोड़ दिए गए हैं।
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय को किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1,77,061.47 करोड़ आवंटित हैं।
- कृषि एवं किसान कल्याण को खेती-किसानी और नई योजनाओं के लिए सरकार ने 1,40,528.78 करोड़ का फंड तय किया है।
- शिक्षा मंत्रालय को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए 1,39,289.48 करोड़ का बजट रखा गया है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और नई स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,06,530.42 करोड़ का आवंटन हुआ है।
- संचार मंत्रालय को डिजिटल कनेक्टिविटी और टेलीकॉम सेक्टर के विकास के लिए 1,02,267.02 करोड़ दिए गए हैं।

बजट में विकसित भारत के निर्माण

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना बताते हुए कहा कि इसे हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक सशक्त बनाने का ब्लूप्रिंट करार दिया है।

उन्होंने कहा कि बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत का नारा हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है, जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। उन्होंने कहा

बजट में सुधार हुए हैं नजरअंदाज: राहुल

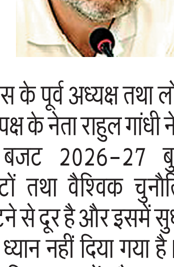

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बजट 2026-27 बुनियादी संकटों तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने से दूर है और इसमें सुधारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को पूरी तरह से नकार दिया गया है। बिना नौकरी के युवा, गिरती मैन्युफैक्चरिंग, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है।

सरकार का मिशन मोड अब चुनौती मार्ग बना: खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बजट को नीतिगत खालीपन, दूरदर्शिता तथा दिशाहीन करार दिया और कहा है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में चुनौतियों का ठोस समाधान करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं। सरकार का मिशन मोड अब चुनौती मार्ग बन चुका है।

आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी नई रफ्तार: मोदी

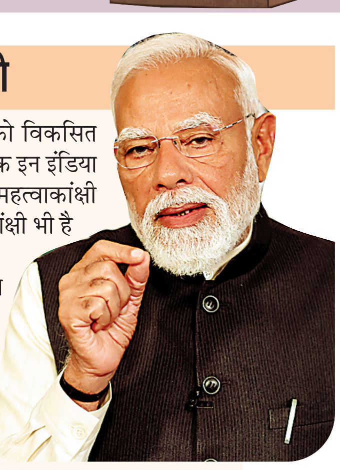

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को विकसित भारत की ऊंची उड़ान का आधार बताया और कहा कि इसमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट महत्वाकांक्षी भी है और देश की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है।

प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी भारत जिस रिफार्म एक्सप्रेस पर सवार है इस बजट से उसे नयी ऊर्जा और नयी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं है और वह जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है।

बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं पर फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026- 27 का बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है. बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है. यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास बजट की मुख्य विशेषता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ होगा.